

प्रेषक

टीकम सिंह पेंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-२

देहरादून : दिनांक २५ फरवरी, २००८

विषय :- ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत हल्दूखाता-मोटाढांग-सिंगड्डी पेयजल योजना के अन्तर्गत कलालघाटी में निर्मित नलकूप के पुनर्विकास, ऊर्जीकरण एवं पाईप लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 4045/वि०अनु०/०२/ अनुदान/२००७-०८ दिनांक ११.१०.२००७ तथा शासनादेश संख्या ५३६/उत्तीस(२)/ ०५-२(१२पे०)/२००६ दिनांक २२.०३.२००६ जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष २००५-०६ में ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत हल्दूखाता-मोटाढांग-सिंगड्डी पेयजल योजना के अन्तर्गत कलालघाटी में निर्मित नलकूप के पुनर्विकास ऊर्जीकरण एवं पाईप लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्यों हेतु कुल लागत रु० ९४.१३ लाख के सापेक्ष रु० २५.०० लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष २००७-०८ में रु० ६९.१३ लाख (रुपये उन्नहतर लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२- स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार ही किशतों में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार उत्तराखण्ड को तुरन्त उपलब्ध करा दी जाय।

३- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक ३१.०३.२००८ तक पूर्ण उपभोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। योजना को उक्त तिथि तक पूर्ण करके शासन को भी इसके कमीशनिंग की सूचना दे दी जायेगी, ताकि शीघ्रताशीघ्र योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सकें।

४- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

- 5- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- 6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। यदि फिर भी लागत में पुनरीक्षण होता है तो उसे जल संस्थान के द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस कार्य को जे0एन0यू0आर0एन0 में न रखा जाय।
- 7- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 8- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
- 9- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। स्थल निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- 10- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद की धनराशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- 11- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 12- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 13- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता " के नामे डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 54/XXVII(2)/08 दिनांक 18 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(टीकम सिंह पंचार)
संयुक्त सचिव

संख्या 87/उन्तीस (2)/07-2(12पे0)/2006 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल।

3. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2 / वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)

उप सचिव